



2026:AHC:17758

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2621/2026

विजय

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- अविनाश पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध सूचनाकर्ता की पत्नी एवं उसकी पाँच वर्षीय पुत्री के गुम होने के संबंध में दर्ज की गई थी। जब पीड़िता बरामद हुई, तब उसका धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने प्रार्थी के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया। जबकि धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने अभियोजन का कथन विकसित करते हुए प्रार्थी के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़िता एक विवाहित महिला है, जिसकी आयु लगभग 36 वर्ष है तथा वह तीन बच्चों की माँ है। उसके चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई तथा उसका हाइमन पुराना फटा हुआ एवं ठीक पाया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि धारा 161 एवं 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं तथा पीड़िता के बयानों से यह प्रतीत होता है कि वह स्वयं प्रार्थी के साथ गई थी, जिससे यह स्पष्ट है कि वह सहमति देने वाली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्षकार थी और प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता को दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 19.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः, प्रार्थी विजय को मुकदमा अपराध संख्या 102/2018, धारा 366, 376 भारतीय दंड संहिता, थाना जानकपुरी, जनपद सहारनपुर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।



v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

27 जनवरी, 2026

मुस्तकीम